इंदौर, शनिवार 18 जुलाई 2026
वर्ष : 5 अंक : 225
पृष्ठ : 6 मूल्य : 2
dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

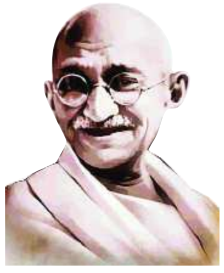

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

कलेक्टर के निर्देश पर जीडीसी के आसपास हुई कार्यवाही

पेज-2

'लॉकअप' देखकर भावुक हुई कुब्रा

पेज-5

भोजशाला के बाहर नमाज कहां होगी

पेज-6

मोदी सरकार के लिखित वादे से पिघला डीएमके का दिल ?

नई दिल्ली (एजेंसी) ● लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और 2029 से महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर मोदी सरकार के लिए राहत भरी खबर है। विपक्ष के अहम सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) इस अहम बिल पर अपने पिछले रुख से पीछे हटते दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में बगावत और शिवसेना (बीटी) में टूट के बाद सरकार के पक्ष में सियासी माहौल मजबूत होता नजर आ रहा है।

पिछले सत्र में इस बिल पर चर्चा के दौरान, सरकार ने छ्स्ब्य को यह आश्वासन देकर मनाने की कोशिश की थी कि लोकसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व में 50% की वृद्धि की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सत्र में जो बात मौखिक रूप से कही थी, माना जा रहा है कि सरकार अब उस वादे को बिल के ड्राफ्ट में लिखित रूप से शामिल कर सकती है ताकि हिचकिचा रहे दलों को भरोसा दिलाया जा सके। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी)के पास 8 सांसद हैं, और उनकी तरफ से भी बिल पर अपना स्टैंड बदलने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही, राज्यसभा में भी सरकार के लिए संख्या बल काफी सकारात्मक नजर आ रहा है।

आगे क्या है सरकार की रणनीति?

सरकार ने फिलहाल इस बिल को दोबारा लाने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सदन में जरूरी संख्या बल सुनिश्चित होते ही इसे फिर से पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि अप्रैल में इस बिल को 298 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ था।

डीएमके ने कांग्रेस को याद दिलाया 'धोखा'

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिया गठबंधन के फैसले के खिलाफ जाने पर जब कांग्रेस ने छ्स्ब्य को नसीहत दी, तो द्रविड़ पार्टी के सूत्रों ने कांग्रेस पर ही गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगा दिया। डीएमके के एक सूत्र ने कहा, 'कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बर्बाद किया है। उन्होंने हमारे समर्थन से विधानसभा में पांच सीटें जीतने के बाद विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी के साथ गठबंधन करके डीएमके को धोखा दिया है। इसलिए उन्हें हमें उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। 'डीएमके ने साफ किया है कि भले ही वह अपनी चिंताओं को दूर करने वाले परिसीमन योजना का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन वह पिछली बार की तरह कांग्रेस के रुख का आंख मूंदकर पालन बिल्कुल नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों ने 1997 का जिक्र करते हुए कहा, 'कांग्रेस का इतिहास अपने सहयोगियों को धोखा देने का रहा है। उन्होंने पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों से मिलीभगत का बेबुनियाद आरोप लगाकर आईके गुजराल सरकार से समर्थन वापस लिया और मामूली सी बात पर यूनाइटेड फ्रंट को तबाह कर दिया था।'

सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर-मंतर से अस्पताल पहुंचाया

नई दिल्ली (एजेंसी) ● पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। जंतर-मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि बिना सहमति के उनके मुँह या नसों के ज़रिए कुछ भी नहीं दिया जाए। गीतांजलि ने एक्स पर लिखा, 'मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूँ, जहाँ सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। कृपया उन्हें मुँह के ज़रिए या नसों के माध्यम से कोई भी दवा या तरल पदार्थ तब तक न दिया जाए, जब तक मुझसे, उनके परिवार से और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नज़र रख रहे डॉक्टरों से सहमति न ले ली जाए।'

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से घोषणा की गई है कि अभिजीत दीपके बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

सीजेपी ने कहा है, '20 जुलाई को प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार निकाला जाएगा। पूरे वाक़ये पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि वह थोड़ी देर के लिए धरना स्थल से बाहर गए थे।

उन्होंने बताया, 'जब मैं यहाँ से सुबह सात बजे फ़्रेश होने के लिए निकला तभी पुलिस के लोग आए और सोनम सर को घसीटकर ले गए। भूख हड़ताल पर बैठे 60 साल के शख़्स को पुलिस जबरदस्ती ले गई। जब मैं अपने दोस्त के घर से जंतर-मंतर की ओर आ रहा था, तभी मुझे ख़बर मिली कि सोनम सर को पुलिस ले गई।'

उन्होंने कहा, 'पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की। मैं विदेश से अपने देश लौटा हूँ तो क्या मैं अपराधी हूँ?'

डीसीपी नई दिल्ली ने इस मामले की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है, 'दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें ज़रूरी मेडिकल देखभाल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है।'

न्यूज ब्रीफ

- पंजाब-हरियाणा पुलिस का बड़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन, अंगोला में 2 कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार
- कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात
- लॉरेंस बिश्नोई के भाई आरज़ू बिश्नोई ने अभिनेता आमिर खान को दी धमकी
- कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब 'शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन' हुआ
- ईरान के कई शहरों में धमाके, होर्मुज से गुजरने वाले दो टैंकरों में ब्लास्ट के बाद लगी आग
- अमेरिका ने लगातार सातवीं रात किया ईरान पर भीषण हमला
- RBI की बड़ी तैयारी : देश में अगले साल से आ सकते हैं प्लास्टिक के नोट, 10 और 20 रुपये से होगी शुरुआत
- सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट : सोना 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम व चांदी 2,22,500 रुपये प्रति किलो पर पहुंची

जनगणना में खुलेगी प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की पोल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● आपका खुद का मकान है और नगर निगम आपके यहां पानी सप्लाई कर रही है... ऐसे में यदि आप नगर निकाय को प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपका नाम की अब लिस्ट तैयार हो रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर की चोरी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना के दौरान प्रगणकों (एन्यूमरेटर) से विशेष सर्वे कराया जाएगा, जिसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लागू होने के बावजूद कर जमा नहीं किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगरपालिका और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुताबिक, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में फिलहाल करीब 55 लाख घर हैं और इस सर्वे के माध्यम से नए बने मकानों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा।

नल कनेक्शन और वाटर टैक्स का भी होगा सत्यापन

सर्वे के दौरान यह भी जांच होगी कि किसी भवन में नगर निकाय का जल कनेक्शन है या नहीं, वह चालू है या बंद, और मीटर की क्या स्थिति है। प्रगणक संपत्ति कर और जलकर की आईडी भी पूछेंगे, ताकि नगर निकाय के रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जा सके।

बढ़ेगा नगर निकायों का राजस्व

सरकार का मानना है कि इस अभियान से बिना पंजीकृत संपत्तियों की पहचान होगी, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स और जल उपभोक्ता शुल्क का रिकॉर्ड वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो सकेगा।

आधुनिकता की ओर बढ़ता इंदौर
शहर की खूबसूरती और विकास को दर्शाती विहंगम तस्वीर

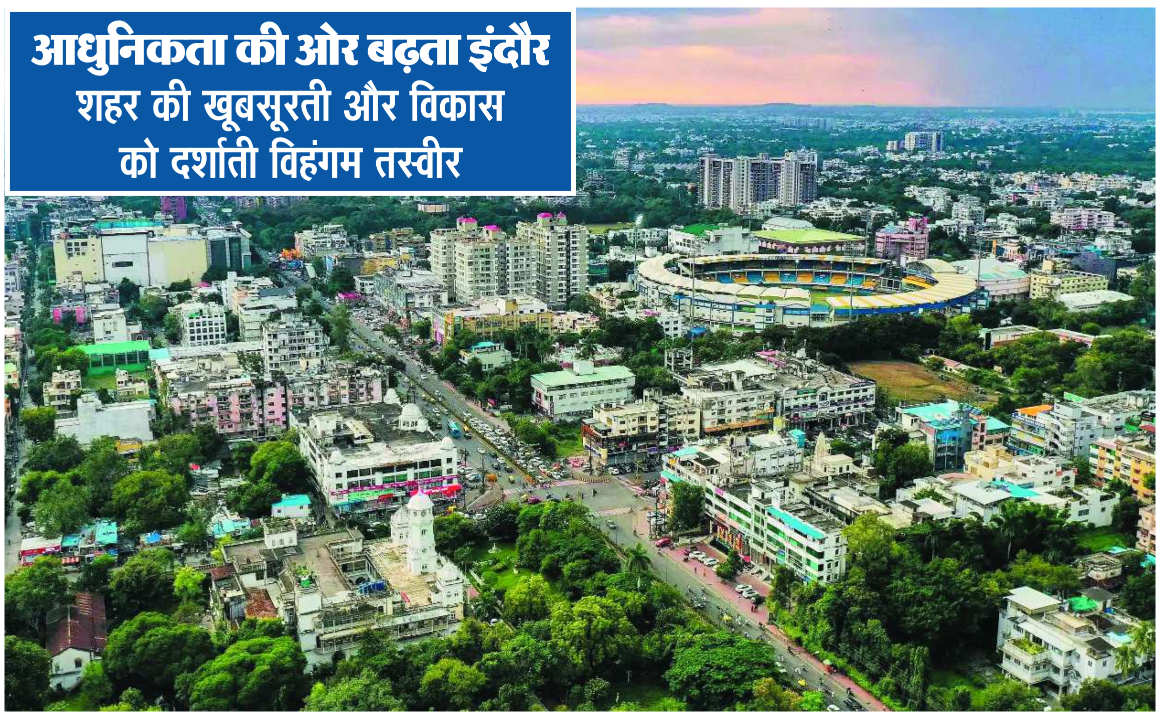

भगवान श्रीकृष्ण पर टिप्पणी, मौलाना के खिलाफ एफआईआर की मांग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● भैय्यू महाराज की पत्नी आयुषी ने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर एक मौलाना के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या आराध्य का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। आयुषी देशमुख ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपनी संस्था के माध्यम से संबंधित मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगी। आयुषी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म या भगवानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो।

कांग्रेस से भाजपा में गए नेता अब भी खाली हाथ

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

राजनीति में कब और कहां कौन सा ऊंट किस करवट बैठ जाए यह कहना आज के दौर में मुश्किल है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस लगातार 20 साल से अधिक सत्ता से बाहर है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के कांग्रेस में रहे दिग्गज नेताओं की, जिन्होंने समय-समय पर कांग्रेस का खूब उपयोग किया। टिकट लाने से लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने तक कांग्रेस पार्टी की जमकर खातिरदारी की, लेकिन कमलनाथ सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने धीरे-धीरे कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामना शुरू कर दिया, जिसमें इंदौर के कहीं दिग्गज नेता शामिल है।

पंकज संघवी, पूर्व विधायक विशाल पटेल, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, अक्षय कांति बम और शिक्षाविद नेता स्वप्निल कोठारी, जिन्होंने इंदौर शहर में कांग्रेस के लिए दमदारी से किला लड़ाया था, लेकिन 18 महीने बाद कमलनाथ सरकार गिरते ही इन नेताओं का कांग्रेस से मोह खत्म हो गया। पंकज सांघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, महापौर से लेकर लोकसभा तक इन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन इनके नसीब में जीत नहीं आई। इतना ही नहीं पंकज के रिश्ते कैलाश से पारिवारिक रहे। इसी का फायदा उठाकर वह भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए अक्षय कांति बम ने कांग्रेस का बम एन वक्त पर फोड़ा और चलते चुनाव में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए। बम दिग्विजय सिंह के करीबी रहे हैं, लेकिन वर्तमान हालातों में कैलाश विजयवर्गीय के दाएं-बाएं नजर आते हैं। पूर्व विधायक संजय शुक्ला के पिता से लेकर भाई तक पूरा परिवार भाजपाई है, लेकिन शुक्ला ने शुरू से ही कांग्रेस से राजनीति की कमलनाथ सरकार में वह विधायक बने, लेकिन एक मामले में उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। विधायक रहे तब एक नंबर विधानसभा में शुक्ला ने जमकर पैसा बहाया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की उम्मीदवारी ने उन्हें 50000 से अधिक वोटो से चुनाव हरा दिया। पूर्व विधायक विशाल पटेल के पिता जगदीश पटेल देपालपुर से दो बार विधायक रहे हैं। दमदार नेताओं में जगदीश पटेल की गिनती होती थी। उसी राह पर विशाल पटेल भी देपालपुर में विधायक बने, लेकिन संजय के साथ वह भी भाजपा में शामिल हो गए। संजय और विशाल रिश्ते में जीजा साले हैं, प्रॉपर्टी व्यवसाय से लेकर कही प्रोजेक्ट में दोनों पार्टनर भी हैं। शिक्षाविद नेता स्वप्निल कोठारी कमलनाथ के भरोसेमंद नेता थे। पांच नंबर विधानसभा से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन वहां से पार्टी ने सत्यनारायण पटेल को उम्मीदवार बनाया।

चुनाव बाद कोठारी ने भी कांग्रेस को राम-राम बोल दिया। जानकारी में पता चला है। इंदौर के एक नेता ने कोठारी की सेटिंग मुख्यमंत्री से बिठाई है। कोठारी के कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को देखा गया। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं का भविष्य भाजपा में अब उज्जवल होगा या फिर सत्ताधारी नेता बनकर केवल पार्टी की सेवा करेंगे, क्योंकि इन नेताओं को कांग्रेस ने पद प्रतिष्ठा के साथ विधायक, सांसद, महापौर तक के टिकट दिए थे। जीत-हार एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सब कुछ दिया। इंदौर में भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम है, पद पाने के लिए कई नेता लाइन में लगे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को क्या भाजपा भुना पाएगी? यह देखना अभी बाकी है।

भाजपा में कार्यसमिति, प्रकोष्ठों की नियुक्तियां एक महीने टलीं

संयोजकों की संख्या सीमित रखने पर जोर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश भाजपा संगठन में कार्यसमिति की पहली बैठक और प्रकोष्ठों की नियुक्ति का मामला अब एक महीने और आगे बढ़ गया है।

दतिया में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के कारण सत्ता-संगठन के सभी नेता चुनावी रणनीति की जमावट में जुट गए हैं। कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित, प्रकोष्ठ संयोजक और सदस्यों की नियुक्ति फिलहाल टाल दी गई है। सदस्यों की संख्या सीमित रखने का फैसला हुआ है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा का मानसून सत्र भी प्रस्तावित है। दतिया में 30 जुलाई को मतदान और चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। इसके बाद ही नियुक्तियां और बैठक की नई तारीख तय हो पाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछले साल 2 जुलाई को पार्टी की कमान संभाली थी। उन्होंने ओरछा में कार्यसमिति की पहली बैठक 18-19 जुलाई तय की थी लेकिन दतिया उपचुनाव के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कार्यसमिति के लिए विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची और करीब आधा दर्जन प्रकोष्ठों में संयोजकों व सदस्यों की नियुक्तियों का ऐलान होना बाकी है।

न्यूज ब्रीफ

ऊर्जस एप से उपभोक्ताओं की मदद

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मोबाइल एप ऊर्जस उपभोक्ताओं की समय पर मदद कर आपूर्ति सुधार को लेकर राहत दिला रहा हैं। पिछले चौबीस घंटे के दौरान ऊर्जस एप के माध्यम से 130 उपभोक्ताओं की मदद की गई। इसमें से इंदौर शहर के 77 उपभोक्ताओं ने ऊर्जस एप पर आपूर्ति संबंधित शिकायतों का समाधान कर राहत पाई। खरगोन, धार, उज्जैन, देवास, रतलाम के उपभोक्ताओं द्वारा भी ऊर्जस मोबाइल एप का उपयोग कर बिजली सेवाओं, शिकायत निवारण सुविधा का लाभ लिया जा रहा हैं।

मानसून काल में भी शहर में बिजली की भारी मांग

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मानसून काल के दौरान भी इंदौर शहर में बिजली की भारी मांग की स्थिति हैं। इंदौर शहर में जुलाई माह के तीसरे सप्ताह के दौरान बिजली की मांग साढ़े पांच सौ मैगावाट के पार दर्ज हुई हैं। सोलह जुलाई को शहर में बिजली की अधिकतम मांग 567 मैगावाट दर्ज हुई हैं, इस दिन आपूर्ति 1 करोड़ 26 लाख यूनिट रही। मांग एवं आपूर्ति दोनों ही तुलनात्मक रूप से ज्यादा रही। जुलाई के सत्रह दिनों में इंदौर शहर में बीस करोड़ यूनिट से ज्यादा बिजली वितरण हो चुका हैं। यह करीब दस प्रतिशत ज्यादा हैं।

जन्माष्टमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक 26 को

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● यादव अहीर समाज केंद्रीय समिति जिला इंदौर के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण भगवान के जन्म रजत जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली परंपरागत जन्माष्टमी शोभा यात्रा रजत जयंती पर्व के आयोजन की तैयारीयां को लेकर समाज के प्रमुख संगठनों की बैठक रविवार 26 जुलाई को शाम 5 बजे स्थिति स्काउट मैदान सभागृह में आयोजित की जाएगी।

20 से 22 जुलाई तक इंदौर में जुटेंगे देशभर के ब्यूटी और हेयर एक्सपर्ट्स

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स, हेयर आर्टिस्ट्स, मेकअप एक्सपर्ट्स और उभरती प्रतिभाओं के लिए इंदौर जल्द ही देश के सबसे बड़े मंच का गवाह बनने जा रहा है। 20 से 22 जुलाई तक फीनिक्स सिटाडेल मॉल में नेशनल आर्टिस्ट्स चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तीन दिन तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में देशभर से आने वाले आर्टिस्ट्स,ब्यूटी प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ब्रांड्स एक ही मंच पर नज़र आएंगे। इस आयोजन में 10 हजार विजिटर्स, 500 प्रतिभागी, 50 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और कई प्रमुख ब्रांड्स की भागीदारी रहेगी। 20 जुलाई को पद्मश्री अनुराधा पौडवाल नेशनल आर्टिस्ट्स चैंपियनशिप 2026 की शोभा बढ़ाएँगी।

मेट्रो निर्माण से आक्रोश, लोग बोले- घरों में भूकंप जैसे झटके, रात में चलती हैं मशीनें

मल्हारगंज के रहवासियों का प्रदर्शन, मकानों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मल्हारगंज क्षेत्र में मेट्रो निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को रहवासियों और व्यापारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि मेट्रो निर्माण में भारी मशीनों के उपयोग से उनके मकानों में लगातार कंपन हो रहा है, जिससे दीवारों में दरारें पड़ रही हैं और घरों का प्लास्टर झड़ने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने, मकानों का सुरक्षा ऑडिट कराने और हुए नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की।

सुबह से रात तक चल रहीं भारी मशीनें रहवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सुबह करीब पांच बजे से रात 11 बजे तक भारी मशीनों से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में कंपन महसूस होता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। उनका आरोप है कि लगातार शिकायतों और ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

विरोध के बीच कुछ देर तक रुका रहा निर्माण कार्य

प्रदर्शन के दौरान रहवासियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लोगों ने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इधर, प्रदर्शन के दौरान विरोध को देखते हुए निर्माण कार्य कर रही ठेका कंपनी ने कुछ समय के लिए काम रोक दिया था। हालांकि बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया गया, जिससे रहवासियों में नाराजगी और बढ़ गई। इस पूरे मामले में इंदौर मेट्रो परियोजना के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। रहवासी अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रभावित मकानों का स्वतंत्र तकनीकी सर्वे कराया जाए, सुरक्षा मानकों की जांच हो और नुकसान होने पर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।

मधुमिलन से छावनी तक आदर्श रोड का किया जाएगा निर्माण

महापौर-विधायक ने किया निरीक्षण

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम द्वारा मधुमिलन चौराहे से छावनी चौराहे तक बनाई जा रही मास्टर प्लान सड़क का शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं विधायक ने निरीक्षण किया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बारिश के ऐन पहले शुरू हुए इस सड़क के निर्माण कार्य से लोगों को परेशानी की आशंका थी, लेकिन आज निरीक्षण के दौरान नागरिकों से संवाद करने पर यह स्पष्ट हुआ कि निगम द्वारा जिस गति और समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है, उससे लोग संतुष्ट हैं। इस दौरान महापौर ने सडक़ निर्माण की प्रगति का जायजा लिया तथा अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की।

तेज गति से हो रहा काम

अब तक 500 मीटर से अधिक की सड़क लेन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य भी तेज गति से जारी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज नेटवर्क एवं पेयजल पाइपलाइन जैसे महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य भी समानांतर रूप से किए जा रहे हैं। महापौर ने निगम के इंजीनियरों एवं अधिकारियों की महापौर ने बताया कि निर्माणाधीन मार्ग पर सराहना करते हुए कहा कि पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया है।

अन्नपूर्णा मंदिर पर 51 फीट ऊंचे हाईड्रोलिक रथ की सजावट का काम आज होगा शुरू

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● अन्नपूर्णा मंदिर से रविवार 19 जुलाई को दोपहर 1 बजे निकलने वाली इस्कॉन मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वृन्दावन से भगवान का रथ और उसके श्रृंगार की सामग्री शुक्रवार को निपान्या स्थित इस्कॉन मंदिर पहुँच गई है।

स्कॉन इंदौर के अध्यक्ष स्वामी महामनदास के निर्देशन में 51 फीट ऊँचे हाईड्रोलिक रथ पर भगवान श्रीकृष्ण, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह विराजित कर वृन्दावन से आई पोशाक से श्रृंगारित करने का काम शनिवार से प्रारम्भ हो जाएगा। यात्रा मार्ग की सफाई स्वर्ण से निर्मित 8 झाडुओं से विशिष्ट अतिथियों द्वारा की जाएगी। शुक्रवार की शाम को अन्नपूर्णा मंदिर से महू नाका चौराहा तक इस्कॉन के संतों और गुरुकुल में पढने वाले वेदपाठी पंडितों ने स्वामी महामनदास के सानिध्य एवं अन्नपूर्णा आश्रम के संचालक स्वामी जयेंद्रानंद गिरी के आतिथ्य में मनुहार यात्रा निकालकर भक्तों को रथ यात्रा का न्योता दिया। निपान्या स्थित इस्कॉन मंदिर पर इन दिनों जगन्नाथपुरी की तर्ज पर रथ यात्रा की तैयारियां पूरे चरम पर पहुँच गई है। रथ यात्रा संयोजक हरि अग्रवाल, किशोर गोयल, अशोक गोयल एवं भावेश दवे ने बताया कि रविवार को निकलने वाली रथ यात्रा के लिए भगवान की पोशाक एवं अनेक किस्म के फूल भी वृन्दावन से आ गए हैं। यात्रा में राधा कृष्ण के स्वरुप में अनेक श्रद्धालु और इस्कॉन मंदिर से जुड़े देश-विदेश के संत भी शामिल होंगे। रथ को ऊपर-नीचे खिसकाने की व्यवस्था प्रमुख रथ की ऊँचाई 51 फीट है जिसे हाईड्रोलिक की मदद से ऊपर-नीचे खिसकाकर बिजली के तारों एवं अन्य अवरोधों से बचाया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मी वैंकटेश देवस्थान का भव्य स्वागत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री मालव खांडल विप्र समाज इंदौर शाखा सभा द्वारा देश की तीसरी पारम्पारिक गौरवशाली रथयात्रा निकली श्री लक्ष्मी वैंकटेश देवस्थान का भव्य स्वागत किया गया। इंदौर शाखा सभा के अध्यक्ष विजय पांडे, प्रदेश संगठन अध्यक्ष, मनीष बणसिया, महिला शाखा सभा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीतल मिश्रा ने बताया कि नृसिंह बाजार चौराहे पर इस वर्ष देश की तीसरी पारम्पारिक गौरवशाली रथयात्रा निकली श्री लक्ष्मी वैंकटेश देवस्थान का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पिपरा समाज द्वारा पांच क्विटंल गुलाब के फूल से भव्य स्वागत किया गया। वहीं समाज के महिलाओं एवं पुरुषों ने दो सौ किलों नमकीन, मिठाई प्रसाद शुद्ध पानी की बाटल का वितरण किया गया।

अशोक यादव | ओमप्रकाश धीमान | राजेन्द्र सोनी | सीमा सेन | हुकुम यादव

आजाद-तिलक अलंकरण से 5 विभुतियां होगी सम्मानित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● नेताजी सुभाष मंच व श्री गीता रामेश्वरम् ट्रस्ट एवं अ.भा. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वाधान में 23 जुलाई 2026, गुरुवार को प्रात: 10 बजे, इंडियन कॉफी हाउस पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रीगल चौराहा, इन्दौर पर भारत के अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती एवं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की 170वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर शहर की 5 विभुतियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन समाजसेवा में लगा दिया। आयोजन की अध्यक्षता अ.भा. कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल करेंगे।

कलेक्टर के निर्देश पर जीडीसी के आसपास हुई कार्यवाही

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मोती तबेला स्थित शासकीय जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीडीसी) की छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर सुश्री श्रुति अग्रवाल ने पुलिस बल के साथ आज महाविद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया।

छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएँ सुनी गईं तथा सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। संभावित ईव-टीजिंग एवं असामाजिक गतिविधियों वाले स्थानों का चिन्हांकन कर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गईं। सुरक्षा की दृष्टि से कॉलेज के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाने वाले ठेलों एवं टपरियों को हटाने की कार्रवाई की गई।

कॉलेज समय के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के साथ एफआरवी की नियमित तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। नियमित पुलिस पेट्रोलिंग एवं सघन निगरानी के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। महाविद्यालय के पिछले प्रवेश द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

सामान्य भविष्य निधि का वार्षिक लेखा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक लेखा विवरण अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। इससे अभिदाता अब घर बैठे अपने GPF खाते का वार्षिक विवरण देख एवं डाउनलोड कर सकेंगे। अभिदाता अपनी शिकायत दूरभाष 0751-2432457 तथा व्हाट्सएप नंबर +91-8827409410 पर भी दर्ज करा सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर एवं बीईओ को ज्ञापन सौंपा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा एवं नवागत बीईओ श्री सक्षम बरमाटे से उनके कार्यालय में भेंट की और पेंशनरों की समस्याओं के सम्बंध में सार्थक चर्चा कर उन्हें ज्ञापन सौंपे।

वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी भगवतीप्रसाद पंडित ने बताया कि एसोसिएशन की पिछले दिनों की गई मांग पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने ढाई माह से रिक्त बीईओ पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की। इस हेतु उनका पुष्पगुच्छ एवं पुष्पमाला से स्वागत कर अभिनन्दन किया और उनका आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन की ओर से उन्हें दो ज्ञापन दिए गए।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर देपालपुर न्यायालय परिसर में हुआ वृक्षारोपण

जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान बोले-प्रकृति की रक्षा ही आने वाली पीढ़ियों के प्रति सच्चा न्याय है

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

देपालपुर ● अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय, देपालपुर परिसर में तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालयीन कर्मचारियों व पक्षकारों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधरोपण किया।

इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि मानव, समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही न्याय का मूल स्वरूप है। वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। जिस प्रकार न्याय व्यवस्था समाज में संतुलन, विश्वास और सुरक्षा स्थापित करती है, उसी प्रकार वृक्ष धरती को जीवन, शुद्ध वायु, हरियाली और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करते हैं।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीनियर सिविल जज रिजवाना कौसर दिव्या श्रीवास्तव इस अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के अध्यक्ष/ प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजय श्रीवास्तव के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को व्यवहार न्यायालय, देपालपुर में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) से संबंधित चेक बाउंस के आपराधिक प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों के राजीनामे के माध्यम से निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। विशेष लोक अदालत के लिए दो खंडपीठों का गठन किया गया है। पहली खंडपीठ में प्रथम जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान के साथ अधिवक्ता जितेंद्र वर्मा तथा दूसरी खंडपीठ में सिविल जज वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रिजवाना कौसर के साथ अधिवक्ता पियूष बाथम सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। तहसील विधिक सेवा समिति ने सभी अधिवक्ताओं एवं चेक बाउंस प्रकरणों के पक्षकारों से अपील की है कि वे 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सहमति एवं राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण, त्वरित एवं स्थायी निराकरण कर न्यायालयीन समय, धन और श्रम की बचत करते हुए न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग प्रदान करें।

गोल्डन जुबली समारोह सम्पन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● गुजराती कालेज इन्दौर मे वर्ष 1976 मे बी काम प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र - छात्राओं ने अपने ग्रुप गुजराती कामर्स कालेज साथी ग्रुप इन्दौर के तत्वावधान में 'प्रवेश के 50 वर्ष' के नाम पर गोल्डन जुबली समारोह दिनांक 12 जुलाई 2026 को भंडारी फार्म एवं रिसोर्ट कनाड़िया जंक्शन बायपास रोड पर आयोजित किया। कार्यक्रम में सहपाठी सपरिवार जीवनसाथी, परिजनों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सहपाठी - मोहित भारूका, राजेन्द्र मकवानी, कमलेश शर्मा, ओम प्रकाश असावा, अल्पेश शाह,परेश देसाई, महेश सेठिया, विपिन शाह, राजेन्द्र पटेल सहित आदि उपस्थित रहे।

इंदौर जिले की 10 स्वास्थ्य संस्थाएं सम्मानित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राष्ट्रीय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कायाकल्प अवार्ड में इंदौर जिले की 10 स्वास्थ्य संस्थाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। इन संस्थाओं ने स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा मरीजों की संतुष्टि जैसे मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

केयर सीएचएल में 49 वर्षीय महिला के इन्सीजनल हर्निया का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हुआ उपचार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● हर्निया का बार-बार लौटना सर्जनों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। खासकर तब, जब मरीज पहले कई बार ऑपरेशन करा चुका हो। ऐसा ही एक मामला केयर सीएचएल हॉस्पिटल, इंदौर में सामने आया, जहां 49 वर्षीय महिला के चौथी बार हुए जटिल इन्सीजनल हर्निया का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से उपचार किया गया। महिला मरीज करीब 20 सेंटीमीटर की पेट की सूजन के साथ अस्पताल पहुंची थीं। उनकी पहले तीन बार हर्निया की सर्जरी हो चुकी थी। इसके अलावा उन्हें कई बार आंतों में रुकावट (सब-एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन) की समस्या भी हुई थी। जांच में दोबारा हुए इन्सीजनल हर्निया की पुष्टि हुई, जिसमें आंतें हर्निया की थैली के भीतर पहुंच चुकी थीं।

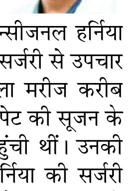

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

इंदौर, शनिवार 18 जुलाई 2026

अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं हटाई तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना

भोपाल (एजेंसी) ● शहर से गांव की ओर जाने वाले हाईवे और सड़कों के किनारे सस्ते प्लॉट के लुभावने विज्ञापन आम हैं। इनके झांसे में आकर लोग जमा-पूंजी से प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कॉलोनी के लिए डायवर्शन या टीएनसीपी जैसी जरूरी मंजूरियां नहीं ली गईं। कई कॉलोनियां खेतों की अवैध प्लाटिंग कर बसाई जाती हैं, जहां सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होतीं। ऐसे भ्रामक विज्ञापन और खेतों की अवैध प्लाटिंग अब कानूनन अपराध होंगे। इन्हें रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 'मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम-2026' लागू करने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

प्रस्तावित कानून का मकसद लोगों को अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने के धोखे से बचाना, वैध कॉलोनियों की मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाना और बिल्डरों के साथ लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। इसके लिए जुर्माने और जेल के सख्त प्रावधान किए गए हैं।

कार्रवाई नहीं करना भी अपराध

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने क्षेत्र में बन रही अवैध या अनधिकृत कॉलोनी की रिपोर्ट नहीं करता या समय पर कार्रवाई नहीं करता, तो इसे अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और उसमें सहयोग माना जाएगा। 6 महीने तक जेल और 10 लाख जुर्माना: दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को छह महीने तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत जुर्माना हो सकता है। तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने वाले सक्षम अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अवैध या अनधिकृत निर्माण हटाने में सहयोग नहीं करने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 'निगरानी एवं पर्यवेक्षण समिति' गठित होगी। समिति हर महीने बैठक कर अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा करेगी।

न्यूज ब्रीफ

श्रद्धा और विश्वास के बिना जीवन में कोई कर्म सार्थक नहीं हो सकता

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सुख में भगवान का सुमिरन नहीं, विस्मरण होता है। दुख भगवान की शरण में पहुंचने का माध्यम है। जिसने दुख को भगवान का प्रसाद या सुख मान लिया वह दुखी हो ही नहीं सकता। भागवत का ज्ञान विषाद को प्रसाद में बदल देता है। दुख मानव की सम्पत्ति है, जबकि सुख व्यक्ति को अभिमानी बना देता है। जवानी, ज्ञान, धन, सम्पत्ति और अधिकारों का अहंकार मनुष्य को भक्ति से विमुख बना देता है। दुख का कारण समय, स्वभाव और हमारे कर्म होते हैं। दुख के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, भगवान या कोई और नहीं। श्रद्धा और विश्वास के बिना जीवन में कोई कर्म सार्थक नहीं हो सकता। ये प्रेरक विचार हैं वृन्दावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती के, जो उन्होंने मनोरमागंज स्थित गीता भवन में भक्त मंडल एवं अखंड प्रणव योग वेदांत पारमार्थिक न्यास के तत्वावधान में चल रहे भागवत ज्ञान यज्ञ में बालक ध्रुव की भक्ति की व्याख्या के दौरान व्यक्त किए।

मुद्रा शास्त्री गिरीश शर्मा आदित्य की नई छलांग, अमेरिका ने भी दिया आइकॉन सम्मान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राष्ट्रीय मुद्रा परिषद के संयोजक और शहर के वरिष्ठ मुद्रा शास्त्री गिरीश शर्मा आदित्य को संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन सम्मान 2026 से अलंकृत करते हुए वहां की संस्था इकोहग एलएलसी ने मुद्रा शास्त्री के रूप में उनके उत्कृष्ट योगदान, सिक्कों एवं मुद्रा विरासत के अध्ययन, संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार के प्रति उनके समर्पित प्रयासों के लिए सम्मानित किया। उन्हें इसके पूर्व 45 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुके हैं लेकिन किसी विदेशी संस्था की ओर से मिलने वाला यह पहला महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्हें यह सम्मान पत्र अमेरिका के वायोमिंग राज्य की उक्त संस्था द्वारा अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में यूएस स्माल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम फॉर अवार्ड मैनेजमेंट तथा अन्य संस्थाओं की भागीदारी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया।

बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2026 को मध्यप्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी , भोपाल में 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन में बाल कल्याण समिति की भूमिका' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

कार्यक्रम रामेन्द्र सिंह, महासचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, मध्यप्रदेश। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. अनिल कोठारी, गहानिदेशक, मध्यप्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल तथा श्रीमती सुधा विजय सिंह भदौरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला न्यायालय, भोपाल, आयोग की सदस्य श्रीमती सोनम निनामा एवं श्रीमती अर्चना गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति रही। बाल कल्याण समितियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना मुख्य उद्देश्य कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश की समस्त बाल कल्याण समितियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता स्थापित करना, सदस्यों की विधिक एवं पुक्रियागत दक्षता का संवर्धन करना, विभिन्न जिलों के अनुभवों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना तथा राज्य की वाल संरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं 'बालहित सर्वोपरि' के सिद्धांत के अनुरूप सुटढ़ बनाना था।

इंदौर जिले में खरीफ फसलों की स्थिति बेहतर

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जिले में खरीफ सीजन के दौरान कुल 2,52,150 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बोनी की गई है। इसमें सर्वाधिक 2,33,700 हेक्टेयर यानि लगभग 93 प्रतिशत क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की गई है। वर्तमान में जिले की खरीफ फसलों की स्थिति संतोषजनक एवं अच्छी है। किसान फसलों में खरपतवार नियंत्रण तथा नमी संरक्षण के लिए डोरा चलाने एवं अन्य अंतरवर्ती कृषि कार्य कर रहे हैं। जिले में इस वर्ष 17 जुलाई 2026 तक 13.9 इंच वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक केवल 7.2 इंच औसत वर्षा हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग दोगुनी वर्षा होने से खरीफ फसलों को पर्याप्त लाभ मिला है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कृषकों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का वितरण निरंतर किया जा रहा है।

स्वच्छता को लेकर सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयसीमा में कार्य करें : संभागायुक्त

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर इंदौर संभाग में लगातार नवाचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में स्वच्छता संबंधी जनजागरूकता के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। नागरिकों में साफ-सफाई के प्रति चेतना जागी है। अब संभाग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी तेजी से काम हो रहा है। संभागायुक्त डॉ. खाड़े आज एक निजी होटल में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में परिपालन इंदौर संभाग के नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

साईं मंदिर का 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव शुरु, वेद मंत्रो के बीच साईं बाबा का हुआ अभिषेक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सुखलिया स्थित लवकुश आवास विहार में सांई बाबा मंदिर का 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव शुक्रवार से साईं बाबा का अभिषेक हवन पूजन के साथ शुरू हुआ। खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या, स्वास्थ्य शिविर,सम्मान समारोह और विशाल भंडारा,सेवा कार्य सहित विभिन्न आयोजन होंगे। लवकुश आवास विहार सांई बाबा मंदिर समिति अध्यक्ष चन्द्रकांत कुंजीर, करण कुंजीर, मिलिंद दिघे ने बताया कि सुखलिया स्थित लवकुश आवास विहार में सांई बाबा के मंदिर का स्थापना दिवस 3 दिनों तक मनाया जा रहा है। इसमें स्थापना दिवस महोत्सव की शुरुआत शुक्रवार को सुबह सांई मंदिर में विद्वान पंडितों के सानिध्य में साईं बाबा का अभिषेक पूजन अर्चन के साथ की गई और हवन में आहुतियां दी। महोत्सव में निहारिका कुंजीर,रिया कुंजीर, रमेश खेड़े, गोदावरी मोटवानी, रूक्मणी शर्मा, बबलू गुंजाल,सुनील खंडागले संतोष पवार, जीतू अहिरवार, संजय पांडे, राजेंद्र शर्मा सहित अन्य मौजूद थे। महोत्सव में दूसरे दिन 18 जुलाई,शनिवार को विशाल स्वास्थ्य शिविर लगेगा जिसमें इंडेक्स मेडिकल हॉस्पिटल के तत्वाधान में होगा। हजारों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। महोत्सव के तीसरे दिन 19 जुलाई को मुख्य महोत्सव होगा। जिसमे शाम 7:00 बजे से खाटू श्याम बाबा की विशाल भजन संध्या आयोजित की जाएगी इसमें प्रसिद्ध भजन गायक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। साईं बाबा को फलों की वाटिका में विराजित करके 108 दीपों से महाआरती होगी। उसके बाद विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा जिसमें हजारों साईं भक्त महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। सम्मान समारोह में अलग-अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ 3 दिवसीय महोत्सव का समापन 19 जुलाई को होगा।

सांसद शंकर लालवानी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के सदस्य मनोनीत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के अंतर्गत गठित यह केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण वैधानिक बोर्ड है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा उपाध्यक्ष भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार सचिव करते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों, गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म कर्मियों तथा स्वरोजगार से जुड़े नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, श्रमिक कल्याण एवं अन्य नीतिगत विषयों पर केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करता है। देश की कार्यशील आबादी का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यह बोर्ड नीति निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शंकर लालवानी का इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय बोर्ड में मनोनयन इंदौर एवं मध्यप्रदेश के लिए गौरव का विषय है। इससे प्रदेश के लाखों असंगठित श्रमिकों, छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स, ऑटो एवं टैक्सी चालकों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स तथा ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मियों के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आवाज़ मिलेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड समय-समय पर पेंशन, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व लाभ, श्रमिक पंजीकरण, कौशल विकास, बच्चों की शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसाएँ देता है। इन सुझावों के आधार पर श्रमिक हितों से जुड़ी योजनाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाता है।

विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति सभी के प्रति मैत्री और कल्याण का भाव रखने का संदेश देती है। कृष्ण-सुदामा का प्रसंग भी हमें मैत्री के भाव को पूर्ण गरिमा और आत्मीयता के साथ निभाने का संदेश देता है। यह प्रसंग हमें अमीर-गरीब का भेद मिटाकर समरसता का संदेश भी देता है। भगवान कृष्ण का शिक्षा के लिए सांदीपनि आश्रम उज्जैन आगमन और शिक्षा ग्रहण कर उनका 64 कलाओं 14 विद्याओं में पारंगत होना हमें शिक्षा का महत्व बताता है। राज्य सरकार बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सांदीपनि विद्यालयों की सौगात दे रही हैं। प्रदेश के सांदीपनि विद्यालय सर्वसुविधा युक्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का माध्यम बन रहे है। इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। शासकीय शालाओं में बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें और साइकिलें प्रदान की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में टॉप करता है तो उसे स्कूटी दी जा रही है। राज्य में गुरुपूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसीलिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए कुलगुरु संबोधन की परंपरा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्लीमनाबाद कटनी में सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान जारी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभागीय परिवहन सड़क सुरक्षा दस्ता द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूल एवं कॉलेज वाहनों तथा मालवाहक वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। शुक्रवार को सड़क सुरक्षा दस्ता द्वारा राऊ चौराहा एवं बायपास क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लोक परिवहन एवं मालवाहक वाहनों का निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान वाहनों के आवश्यक दस्तावेज, परमिट की शर्तों का पालन, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी, वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। इसके साथ ही बसों में ओवरलोडिंग, यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने जैसी शिकायतों की भी जांच की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों एवं मालिकों को अपने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए भी प्रेरित किया। अभियान के दौरान स्कूल एवं कॉलेज वाहनों की विशेष रूप से सघन जांच की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि विद्यार्थियों के परिवहन में उपयोग किए जा रहे वाहन सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं तथा आवश्यक दस्तावेज एवं परमिट पूर्ण रूप से वैध हैं।

एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में वीर रायफल शूटिंग सोसायटी के छः निशानेबाजों ने जीते रजत एवं कांस्य पदक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●भोपाल में आयोजित 16वीं एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में एक बार फिर प्रदेश के पहले निजी फायर आर्म क्लब, इंदौर की वीर रायफ़ल शूटिंग सोसायटी के 6 निशानेबाजों ने भाग लिया, जिनमें एथलीट्स, वीरहंस शर्मा ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक और रूद्र प्रताप सिंह राठोर ने कांस्य पदक हासिल किया। स्पर्धा में शामिल क्लब के 4 अन्य एथलीट्स, इंद्र विक्रम सिंह बैस, कीर्ति राज सिंह चौहान, जाहिद अली बंदूकवाला एवं सुलेमान शेख ने प्री-नेशनल प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए स्वयं को क्वालिफाई कर लिया। इस तरह क्लब के 6 एथलीटों ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर शहर एवं सोसायटी का नाम रोशन किया है। सोसायटी के प्रमुख एवं कोच सतीश शर्मा ने सभी निशानेबाजों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

तीन हफ्ते से अनशन पर सोनम वांगचुक, बिगड़ती सेहत: क्या सरकार की चुप्पी ही असली परीक्षा है?

सरकार को उनसे बातचीत करना और अनशन खत्म कराना जरूरी नहीं लग रहा है। सवाल है कि सरकार के ऐसे रुख को लोकतंत्र के आईने में किस नजरिए से देखा जाएगा। किसी भी लोकतंत्र में जनता की ओर से अगर सरकार के रुख या उसकी नीतियों पर सवाल उठाया जाता है, तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वाभाविक स्थिति है। ऐसे में सरकार का दायित्व होता है कि वह उन सवालों पर विचार करे, हर संभव और संतुष्ट करने वाला उचित उत्तर दे। विडंबना यह है कि कई बार सरकार की ओर से जन-आंदोलनों को लेकर उदासीनता या फिर उपेक्षा का भाव दिखाया जाता है और इसी वजह से कोई समस्या सुलझने के बजाय और ज्यादा जटिल हो जाती है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में जब युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया, तभी सरकार को उनके साथ बातचीत करके कोई समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सरकार की अनदेखी के बाद भी जिस तरह लोगों ने इस मसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को उठाना जारी रखा है, उससे साफ है कि वे फिलहाल इसे एक प्रतीकात्मक हल की तरह देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि सरकार को आंदोलनकारियों के साथ संवाद स्थापित करके कोई रास्ता निकालना जरूरी नहीं लग रहा। हालांकि सरकारी उदासीनता के बावजूद प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन अभी जारी है और अब कई नेता भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मगर इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन के साथ जुड़ने और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन को नई गति मिली है और वे अपनी मुख्य मांग पूरी करने पर जोर दे रहे हैं। मगर यह चिंता की बात है कि करीब तीन हफ्ते से लगातार अनशन पर रहने की वजह से जहां सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं सरकार को उनसे बातचीत करना और अनशन खत्म कराना जरूरी नहीं लग रहा है। सवाल है कि सरकार के ऐसे रुख को लोकतंत्र के आईने में किस नजरिए से देखा जाएगा। क्या यह सरकार के लिए एक शर्मिंदा करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय को यह याद दिलाना पड़ रहा है कि अनशन पर बैठे एक आंदोलनकारी को लेकर सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए? गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर हर रोज नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सीय मदद मुहैया कराएं।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता का 'इथेनॉल पथ': उम्मीदों की उड़ान और व्यावहारिक अवरोध

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जुझारूपन ने फरवरी से दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया है, और मोदी सरकार की कारों में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाने की आवश्यकता का कुछ लोगों द्वारा उपहास किया गया है क्योंकि 'दूध में पानी की मात्रा बढ़ाने से दूध की मांग कम हो जाएगी'। लेकिन सरकार की इस सोच में कुछ भी गलत नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करने के प्रयोग पूरी दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए यह सही है कि भारत में इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो तेल आयात पर निर्भर है ।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं के एक अभूतपूर्व चौराहे पर खड़ा है ऐसे समय देश ने हाल ही में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही हासिल कर दुनिया के सामने नीतिगत इच्छाशक्ति का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। वर्ष 2013-14 में जहां इथेनॉल मिश्रण की दर महज 1.5 प्रतिशत के आसपास सिमटी हुई थी, वहीं 2025-26 के कालखंड में इसका देशव्यापी स्तर पर 20 प्रतिशत तक पहुंच जाना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की एक युगांतकारी घटना है? इस नीतिगत उछाल का प्राथमिक श्रेय केंद्र की मोदी सरकार के 'इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम' को जाता है, जिसने भारत को जीवाश्म ईंधनों की विदेशी निर्भरता से मुक्त कराने और 'पंचामृत' के तहत वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लिया है।

परंतु, इस बड़ी नीतिगत सफलता के साथ ही धरातल पर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल और व्यावहारिक चुनौतियां भी सिर उठाने लगी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इस दीर्घकालिक अभियान को कमजोर कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी स्तर पर E20 ईंधन के अनिवार्य प्रसार के बाद से आम उपभोक्ताओं, मोटर वाहन उद्योग और कृषि-अर्थशास्त्रियों के बीच एक त्रिपक्षीय बहस छिड़ गई है। एक तरफ जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत का अचूक हथियार मानती है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक माइलेज में गिरावट और पुराने वाहनों के इंजनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं। ऐसे में यह नीतिगत समीक्षा का सही समय है कि क्या भारत अपनी हरित ऊर्जा की रफ्तार को बनाए रखते हुए आम जनता की चिंताओं को वैज्ञानिक और आर्थिक धरातल पर संतुष्ट कर पा रहा है?

इस नीति की आवश्यकता को समझने के लिए सबसे पहले भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता के आंकड़ों को देखना होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 88.5 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। वैश्विक राजनीति में होने वाले उतार-चढ़ाव, खाड़ी देशों के तनाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भारत के घरेलू बाजार और बजटीय संतुलन को सीधे प्रभावित करती है। सरकार की इस इथेनॉल नीति ने देश की मैक्रो-इकोनॉमी को एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। 2014-15 से लेकर मई 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश ने 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत की है और करोड़ों मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात को घरेलू जैव-ईंधन से प्रतिस्थापित किया है।

इस आर्थिक चक्र का दूसरा सबसे खूबसूरत पहलू इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है। जैव-ईंधन का उत्पादन केवल फैक्टरियों की चहारदीवारी में नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के खेतों से शुरू होता है। गन्ने के उप-उत्पाद (शीरा), मक्का, और टूटे हुए चावल (सरप्लस अनाज) से इथेनॉल बनाने की अनुमति देकर सरकार ने किसानों को केवल 'अन्नदाता' से 'ऊर्जादाता' के रूप में परिवर्तित करने का सफल प्रयास किया है। इस खरीद प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और घरेलू डिस्टिलरीज को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और चीनी मिलों के गन्ना बकाया संकट पर काफी हद तक लगाम लगी है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो श्20 मिश्रण ने देश के वायुमंडल को लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचाया है, जो महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ी राहत है।

नीतिगत स्तर पर जितनी यह योजना आकर्षक और देशहित में दिखाई देती है, उपभोक्ता स्तर पर इसके अनुभव उतने ही मिश्रित रहे हैं। देश के करोड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों द्वारा लगातार यह शिकायत की जा रही है कि श्20 पेट्रोल के उपयोग के बाद से वाहनों के माइलेज में 6 से 7 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात सही भी है; इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग एक तिहाई कम होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि समान दूरी तय करने के लिए इंजन को अधिक ईंधन की खपत करनी पड़ती है। आज के इस महंगाई के दौर में, जब पेट्रोल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, आम नागरिक को कम माइलेज के रूप में अपनी जेब पर अतिरिक्त बोझ महसूस हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी मोर्चे पर सबसे बड़ी चिंता 'मटेरियल डिग्रेडेशन' यानी वाहनों के पुर्जों के खराब होने की है। इथेनॉल स्वभाव से 'हाइग्रोस्कोपिक' होता है, जिसका मतलब है कि यह हवा से नमी और पानी को बहुत तेजी से सोखता है। यह रासायनिक गुण पुराने वाहनों (जो विशेष रूप से श्20 के अनुकूल नहीं बने हैं) के ईंधन टैंक, पाइपलाइन और कार्बोरेटर या इंजेक्टर प्रणालियों में जंग और प्लास्टिक या रबर के पुर्जों के गलने का कारण बन सकता है। यद्यपि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और प्रमुख वाहन निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ने सेवा डेटा का हवाला देते हुए दावा किया है कि E20 से पुराने इंजनों को कोई बड़ा या गंभीर नुकसान नहीं देखा गया है, फिर भी आम जनता के भीतर बैठा अविश्वास और डर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जनता के इसी जमीनी विरोध और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की अपूर्ण तैयारी को देखते हुए मोदी सरकार ने हाल ही में बेहद परिपक्वता और वैज्ञानिक संयम का परिचय दिया है। पहले बाजार में ऐसी अटकलें जोरों पर थीं कि सरकार E20 की तत्काल सफलता के बाद तेजी से 25 प्रतिशत सम्मिश्रण (E25) की ओर बढ़ेगी। परंतु, उपभोक्ताओं के फीडबैक और वाहनों की तकनीकी सीमाओं को स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम और परिवहन मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि E25 को लागू करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सरकार ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि वर्तमान में E20 ईंधन पूरी तरह से सुरक्षित है और उच्च मिश्रणों की तरफ कदम केवल व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों, ऑटोमोबाइल उद्योग की तैयारियों और उपभोक्ताओं की सहमति के बाद ही बढ़ाया जाएगा। सरकार की इस 'ग्रेडेड अप्रोच' की सराहना की जानी चाहिए। किसी भी देशव्यापी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश के अंतिम नागरिक के हितों के साथ कितनी सहजता से मेल खाती है। यदि सरकार बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के जबरन उच्च मिश्रण थोपती, तो इससे न केवल वाहन बाजार में व्यवधान उत्पन्न होता, बल्कि हरित ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रति जनता में एक स्थायी आक्रोश और अविश्वास पैदा हो सकता था।

इस लेख में एक और गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, जो नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वह है-'अन्न बनाम ईंधन' का द्वंद्व। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में खाद्य सुरक्षा हमेशा से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जब हम इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के जूस, मक्का और विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से मिलने वाले चावल का अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं, तो इसका सीधा असर देश के खाद्य बाजार पर पड़ता है। विगत वर्षों में चीनी के घरेलू दामों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार को कई बार इथेनॉल उत्पादन पर अस्थायी प्रतिबंध या सीमाएं लगानी पड़ी थीं, हालांकि बाद में आपूर्ति सामान्य होने पर इन प्रतिबंधों को हटा लिया गया। यदि किसान अनाज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा केवल ऊर्जा क्षेत्र की व्यावसायिक डिस्टिलरीज को बेचने लगेंगे, तो देश में पशुओं के चारे (जैसे मक्के से बनने वाले फीड) और आम जनता के उपभोग वाले खाद्यान्न की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो सकती है। इसलिए, नीति की निरंतरता के लिए कृषि भूमि के उपयोग और फसलों के चक्र का सटीक वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के उज्ज्वल और स्वच्छ भविष्य के लिए एक गैर-परक्राम्य आवश्यकता है, लेकिन इसकी सफलता का रास्ता आम जनता की जेब और भरोसे से होकर ही गुजरता है। इस नीति को बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन रणनीतिक कदमों पर विचार किया जाना चाहिए: उपभोक्ताओं को कम माइलेज के दर्द से राहत देने का सबसे तार्किक तरीका 'मूल्य प्रोत्साहन' है। सरकार को E20 या भविष्य के उच्च इथेनॉल मिश्रित ईंधनों की कीमत शुद्ध पेट्रोल या legac4 फ्यूल की तुलना में 5 से 7 प्रतिशत कम रखनी चाहिए। जब उपभोक्ता को ईंधन की कीमत में सीधी छूट मिलेगी, तो माइलेज की मामूली कमी की भरपाई आर्थिक रूप से हो जाएगी, और वे स्वेच्छा से पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का चयन करेंगे। जरुरत है सरकार और तेल विपणन कंपनियों को केवल दावों के बजाय प्रयोगशालाओं के प्रामाणिक डेटा को जनता के सामने रखना चाहिए। पुराने वाहनों की देखभाल कैसे करें, इथेनॉल ईंधन के उपयोग के दौरान किन सावधानियों को बरतें, इसके बारे में पेट्रोल पंपों पर ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।तथा खाद्यान्न और गन्ने पर निर्भरता कम करने के लिए पराली, बांस, और कबाड़ से बनने वाले 'सेकंड जनरेशन' (2G) इथेनॉल के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करना होगा। भारत का इथेनॉल कार्यक्रम ऊर्जा स्वतंत्रता और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है। समय से पहले श्20 के लक्ष्य को पाना सरकार के नीतिगत प्रबंधन की जीत है। लेकिन एक जीवंत लोकतंत्र और उपभोक्ता-प्रधान बाजार में किसी भी हरित क्रांति को टिकाऊ बनाने के लिए तकनीकी संवेदनशीलता और जन-आकांक्षाओं का आदर करना अनिवार्य होता है। सरकार ने श्25 पर कदम रोककर और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है, वह स्वागत योग्य है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग जगत, नीति निर्माता और उपभोक्ता मिलकर एक ऐसा पारदर्शी तंत्र बनाएं, जहां देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिक की आर्थिक सुरक्षा दोनों एक साथ सह-अस्तित्व में समृद्ध हो सकें।

अशोक भाटिया, वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार,लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक

कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बलराम कृषि महोत्सव

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए जिले के किसान भाइयों को संबोधित

अजय नलवाया (7879800048)

धार ● दैनिक इंदौर संकेत

कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार जिले में बलराम कृषि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती, मूल्य संवर्धन, आधुनिक कृषि यंत्रों एवं कृषि से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति एवं कृषि आधारित गीतों पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गईं। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत किसानों एवं उपस्थित जनसमुदाय को जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज निर्माण का संदेश दिया गया।इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए जिले के किसान भाइयों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर अधिक आय अर्जित करने तथा आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी किसानों को बलराम कृषि महोत्सव की शुभकामनाएँ भी दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में व्यापक जनसंवाद किया गया है। सभी राजनीतिक दलों, विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी वर्षाकालीन सत्र में आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे।

जिले में बलराम महोत्सव का सफल कार्यक्रम हेतु कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देशन में रहा कलेक्टर द्वारा जिले के कृषकों को प्राकृतिक खेती, कृषि उपज का मूल्यसंवर्धन कर अधिक आय अर्जित करने की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित किया गया

साथ ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर किसानों को पी.एम. कुसुम सोलर-बी योजना के तहत सोलर पम्प स्थापना कर आत्मनिर्भर कृषि की ओर अग्रसर होने की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी उपस्थित रहे कार्यक्रम के दौरान जिले में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं विकासात्मक कार्यों की सराहना की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अभिषेक चौधरी ने किसानों को नवीन फसल चिया सीड्स के उत्पादन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस फसल में नीलगाय से नुकसान की संभावना कम रहती है तथा कम लागत एवं कम श्रम में बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आगामी रबी सीजन में अधिक से अधिक किसानों से चिया सीड्स की खेती अपनाने का आग्रह किया। उप संचालक कृषि विजय चौरसिया द्वारा कपास उत्पादकता मिशन, फसल विविधीकरण, एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में किसानो को जानकारी दी गई कृषि वैज्ञानिक डॉ. नरेश गुप्ता कृषि विज्ञान केन्द्र मनावर द्वारा कृषकों को मिट्टी की उर्वरकता एवं जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपरीत मौसम की परिस्थितियों में फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। उन्होंने 31 जुलाई 2026 से पूर्व अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की। इस आयोजन से विभागीय अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे किसानों को नई तकनीकों एवं योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर प्राप्त हुई। महोत्सव में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, आधुनिक कृषि यंत्र, प्राकृतिक खेती, बलराम तालाब, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण, श्रीअन्न (मिलेट) उत्पाद, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, इफको, कृभको तथा अन्य कृषि सहयोगी संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे किसानों ने उत्साहपूर्वक देखा एवं जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर्स, उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले कृषकों के मेधावी छात्र-छात्राओं, दुग्ध संकलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों एवं संस्थाओं तथा प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापित करने वाले किसानों सहित लगभग 30 हितग्राहियों को प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान प्रदान किया गया। कोरोमण्डल कम्पनी ने किसानों को वैज्ञानिको द्वारा दिये गये व्याख्यान के आधार पर प्रश्न पूछे गये एवं सही उत्तर दिये जाने पर पुरूस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 2,000 से अधिक किसानों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान संगठनों के पदाधिकारियों, कृषि आदान विक्रेताओं तथा कृषि एवं सहयोगी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। बलराम कृषि महोत्सव किसानों के लिए ज्ञान, तकनीक, नवाचार एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रभावी मंच सिद्ध हुआ तथा आत्मनिर्भर एवं समृद्ध कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

तेज धूप से खेत सूख रहे, किसानों को बड़े नुकसान की आशंका

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले नौ दिनों से बारिश पूरी तरह थमी हुई है। लगातार तेज धूप और बढ़ती गर्मी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। शुरुआती बारिश के बाद अच्छी बढ़वार कर रही सोयाबीन की फसल अब नमी की कमी से प्रभावित होने लगी है। खेतों की मिट्टी सूख रही है और कई स्थानों पर फसल मुरझाने के संकेत दिखाई देने लगे हैं।

नमी की कमी से प्रभावित हो रही फसल

बारिश नहीं होने से खेतों में लगातार नमी कम हो रही है। किसान फिलहाल खेतों में खरपतवार हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता फसल को बचाने की है। यदि अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश नहीं हुई, तो सोयाबीन की पैदावार पर गंभीर असर पड़ सकता है।

किसानों की बढ़ी चिंता

किसान महेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि पिछले नौ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे हैं और सोयाबीन की फसल मुरझाने की कगार पर पहुंच गई है। उनका कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आम जनजीवन भी प्रभावित

बारिश थमने के साथ ही जिले में तेज धूप और उमस भरी गर्मी का असर आम जनजीवन पर भी दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग गर्मी से परेशान हैं। किसानों के साथ-साथ आम लोगों की नजरें भी अब मानसून की वापसी पर टिकी हैं।

एटीएम में चोरी का प्रयास नाकाम, सीसीटीवी तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● गोगावां थाना पुलिस ने एसबीआई बैंक के एटीएम में चोरी के प्रयास के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह घटना मोहम्मदपुर तिराहा स्थित एसबीआई एटीएम में 15-16 जुलाई की दरमियानी रात हुई थी। आरोपी ने पुलिस की पहचान से बचने के लिए एटीएम और बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दीपक यादव के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बैंक परिसर और आसपास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।

10-12 साल जूनियर बने वनपाल, 50 वनरक्षकों ने खोल दिया मोर्चा

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● जिले के खरगोन और बड़वाह वन मंडल में वनरक्षकों को वनपाल पद पर दी गई प्रभारी पदोन्नति अब विवादों में घिर गई है। पदोन्नति सूची जारी होने के बाद करीब 50 वनरक्षकों ने प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए वन संरक्षक, खंडवा वृत्त के नाम कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से चेतावनी पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के नियम 11(3) की अनदेखी की गई है।

वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष उदयसिंह सिंगोरिया ने बताया कि कई पात्र और वरिष्ठ वनरक्षकों को पदोन्नति से वंचित कर उनसे 10 से 12 वर्ष कनिष्ठ कर्मचारियों को वनपाल पद का प्रभार दे दिया गया। इससे दोनों वन मंडलों के कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति केवल मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर नियमानुसार की जानी चाहिए थी।

उन्होंने मांग की है कि पूरी पदोन्नति सूची की समीक्षा कर पात्र कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। वनरक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नियमों के अनुरूप संशोधित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे न्यायालय की शरण लेंगे। ऐसे में प्रभारी पदोन्नति को लेकर शुरू हुआ यह विवाद आने वाले दिनों में वन विभाग के लिए बड़ा प्रशासनिक मुद्दा बन सकता है।

भोजशाला : 1 किमी दूर दी जगह, मुस्लिमों ने नहीं पढ़ी नमाज

दैनिक इंदौर संकेत

धार ● भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लिए ग्राम मालीवाड़ा स्थित 40 पीर के पास नमाज पढ़ने जगह चिह्नित की। लेकिन यह व्यवस्था पहले ही दिन विवादों में घिर गई। मुस्लिम समाज ने प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह भोजशाला मंदिर से एक किमी दूर है और सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति शुक्रवार सुबह जिला प्रशासन को मिली। इसके बाद अपर कलेक्टर संजीव केशव पांडे की मौजूदगी में प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच ढाई घंटे चर्चा हुई। प्रशासन ने ग्राम मालीवाड़ा स्थित चालीस पीर के पास खुले स्थान का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में विवादित भोजशाला परिसर के समीप खुले स्थान पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की व्यवस्था करने का निर्देश है, जबकि प्रशासन ने परिसर से एक किमी दूर जगह निर्धारित की है।

फीफा वर्ल्ड कप : विजेताओं के लिए फीफा का खास तोहफा

न्यूयॉर्क (एजेंसी) • फीफा वर्ल्ड कप के विजेता खिलाड़ियों को इस बार एक खास सम्मान मिलेगा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फीफा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। यह रिंग अमरीकी खेलों की मशहूर परंपरा से प्रेरित है और पहली बार फुटबॉल विश्व कप का हिस्सा बनेगी। इसका मकसद खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक जीत की एक खास याद देना है। रिंग के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनी होगी, जबकि दूसरी तरफ विजेता टीम के अनुसार खास डिजाइन तैयार किया जाएगा। हर रिंग पर अलग नंबर होगा, उसे खिलाड़ी के हिसाब से तैयार किया जाएगा और उसके साथ असली होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। फाइनल मैच खत्म होने के तुरंत बाद विजेता टीम के कप्तान और हैड कोच को अस्थायी रिंग दी जाएगी। इसके बाद पूरी विजेता टीम के लिए 30 रिंग तैयार की जाएंगी। हर रिंग को खिलाड़ियों के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा। फीफा ने बताया कि इस रिंग का कुल 2,026 पीस का लिमिटेड एडिशन बनाया जाएगा। इनमें से 30 रिंग विश्व चैंपियन टीम को मिलेंगी,जबकि बाकी 1,996 रिंग दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के लिए आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के रूप में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी।

संन्यास लेने के बाद घरेलू काउंटी टीम के लिए मैदान में वापसी करेंगे बेन स्टोक्स

लंदन (एजेंसी) • अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बेन स्टोक्स अपनी घरेलू काउंटी टीम डरहम के लिए मैदान में वापसी करेंगे। स्टोक्स 21 जुलाई से शुरू होने वाले घरेलू वनडे कप में डर्बीशायर के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। वह डरहम के लिए खेलेंगे और फिटनेस ठीक रहने पर 50 ओवर के मेट्रो बैंक कप और काउंटी चैंपियनशिप सीजन के बाकी सभी मैचों के लिए वह उपलब्ध रहेंगे। उनकी शुरुआत अगले सप्ताह डर्बीशायर के खिलाफ होने वाले मैच से हो सकती है। डरहम के मुख्य कोच रयान कैंपबेल ने कहा, वह अब एक संन्यास ले चुके टेस्ट सुपरस्टार हैं, लेकिन उन्होंने डरहम के क्रिकेटर के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है।

टी20 प्रारुप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर डिविलियर्स ने चिन्ता जतायी

जोहानसबर्ग (एजेंसी) • दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने कहा है कि आईपीएल के सितारों को जमीनी हकीकत समझने की जरुरत है। डिविलियर्स ने टी20 प्रारुप में भारतीय टीम के गिरते हुए प्रदर्शन को लेकर ये बात ही है। डिविलियर्स ने कहा कि आईपीएल में धमाकेदार पारियां खेलने वालों को ये समझना चाहिये कि लीग और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के स्तर में काफी अंतर होता है। उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम लिए बिना कहा कि आईपीएल में रनों का पहाड़ बनाने वाले खिलाड़ियों को अब जमीन पर वापस आने की जरूरत है। माना जा रहा है कि उनका संकेत आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी की ओर था। डिविलियर्स ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हर समय पांचवें गियर में खेलने का खेल नहीं है क्योंकि यहां कमजोर गेंदबाज नहीं मिलते, बल्कि हर प्रतिद्वंद्वी विश्व स्तरीय होता है। डिविलियर्स ने जोर दिया कि बल्लेबाजों को हालातों के अनुकूल ढलते हुए एक या दो से अधिक गियर में खेलना आना चाहिए। उनके अनुसार भारतीय टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड से मिली हार को देखते हुए अब संभल जाना चाहिये।

वहीं भारतीय टीम की हार के बाद से ही मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वह टीम में लगातार बदलाव करते हैं वह टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं डिविलियर्स का मानना है कि केवल कोच को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, बल्कि मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भारतीय प्रशंसकों को सांत्वना देते हुए डिविलियर्स ने धैर्य रखने की अपील की है, क्योंकि टीम इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों की जगह रातों-रात नहीं ली जा सकती। इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के कार्यभार को प्रबंधित करने के कारण द्विपक्षीय सीरीज में अक्सर गेंदबाजी आक्रमण अनुभवहीन दिखता है

नेटफ्लिक्स के लॉक अप: सच या सज़ा में चौथे जजमेंट डे के लिए अर्जुन कपूर की एंट्री

मुंबई (एजेंसी) • नेटफ्लिक्स के कैप्टिव रियलिटी शो लॉक अप: सच या सज़ा के कोर्टरूम में एक नई हस्ती प्रवेश करने वाली है। लोगों के बढ़ते रोमांच के बीच लॉक अप में चौथे जजमेंट डे के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (जनता की आवाज़) के रूप में अर्जुन कपूर एंट्री कर रहे हैं, जो इनमेट्स को स्कैनर के नीचे लाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन, जो मुश्किल सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं, कोर्टरूम की कमान संभालते हैं और इनमेट्स के गेमप्ले, बदलती वफादारियों, टूटे हुए वादों और चौंकाने वाले खुलासों पर सवाल-जवाब करते हैं । चौथे टर्मिनेशन एपिसोड में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रूप में एंट्री करते हुए अर्जुन कपूर ने कहा, ''मुझे हमेशा ऐसी भूमिकाएँ निभाना पसंद रहा है, जहाँ सामने वाले को समझना, उन्हें चुनौती देना और हर पल सतर्क रखना पड़ता है । इनमेट्स सच्चाई की अपनी कहानी के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए, लेकिन मेरा काम था उनके हर दावे पर सवाल उठाना, तह तक जाना और यह पक्का करना कि कोई भी बात छिपी न रह जाए। जेल के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण, अनपेक्षित और काफी मनोरंजक था। इस दुनिया का हिस्सा बनकर बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि दर्शक इस हफ्ते होने वाले खुलासों और ट्विस्ट पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।'' अर्जुन कपूर के सवालों का सामना कौन करने वाला है?

'लॉकअप' देखकर भावुक हुईं कुब्रा

मुंबई (एजेंसी) • अभिनेत्री कुब्रा सैत ने रियलिटी शो लॉकअप का एक एपिसोड देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी भावुक प्रतिक्रिया साझा की है। कुब्रा सैत ने बताया कि प्रतियोगी मधुरिमा का सफर देखकर वह भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुब्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उसने मुझे रुला दिया। उन्होंने कहा कि शो देखते हुए उन्हें अपने रियलिटी शो के अनुभव याद आ गए, जिससे यह उनके लिए एक बेहद निजी और भावनात्मक अनुभव बन गया। मधुरिमा की सराहना करते हुए कुब्रा ने कहा कि उन्होंने पूरे शो में शालीनता और मजबूती के साथ खुद को प्रस्तुत किया है। उन्होंने विशेष रूप से मधुरिमा के संयमित व्यवहार और ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी और कभी किसी प्रतियोगी के बारे में गलत बातें नहीं कीं। कुब्रा ने प्रतियोगी आकांक्षा की भी प्रशंसा की और शो में उनकी वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आकांक्षा का व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा है और वह बाहर से शांत लेकिन भीतर से बेहद मजबूत हैं।

उज्जैन संभाग

हर महीने 2 हजार डॉग बाइट के मामले, दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भी बन रहे शिकार

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जहां हर महीने लगभग 2 हजार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे जिले में एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाने की सुविधा केवल चरक अस्पताल में उपलब्ध है। इसके कारण शहर और जिलेभर से आने वाले मरीजों के साथ-साथ महाकाल दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी इलाज के लिए इसी अस्पताल में जाना पड़ता है। अस्पताल में कई बार एक साथ कई डॉग बाइट के मामले पहुंचते हैं। अस्पताल में केवल तीन नर्सें एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाने का काम संभाल रही हैं, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। जिले में कई घटनाएं सामने आई हैं महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक क्षेत्र में भी डॉग बाइट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी प्रभावित होती है। हाल ही में महाकाल मंदिर परिसर में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मी पर भी आवारा कुत्ते ने हमला किया था। हाल के महीनों में जिले में कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। जनवरी 2026 में महिदपुर में एक कुत्ते ने लगभग 40 लोगों को काटा था। जून 2026 में महिदपुर तहसील के देलवाड़ी गांव में एक तीन वर्षीय बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया था। एक महिला अपने बच्चों के साथ स्कूटी से जा रही थी, तभी एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया और वह बच्चों सहित गिर गई थी। जिसमें बोहरा समाज ने इस मामले में निगम को इस बात से अवगत कराया था।

निगम का शेल्टर खाली पड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद शहरवासियों को उम्मीद है कि नगर निगम इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई करेगा। हालांकि, नगर निगम की कुत्तों को पकड़ने और नसबंदी करने की व्यवस्था पूरी तरह बंद है।

निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बेचने वाली दुकान सील, सतवास में बिना वैध दस्तावेज बिक रही थी

दैनिक इंदौर संकेत

देवास • सतवास में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को दुकान कान्हा कलेक्शन को सील कर दिया। यह कार्रवाई निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बिक्री में एकाधिकार को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद की गई। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर डीपीसी अजय मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने सतवास तहसीलदार अवधेश कुमार यादव और थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौजूदगी में दुकान और कुछ निजी स्कूलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदार ने स्वीकार किया कि उसकी दुकान पर 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बेची जा रही थी। वह यह साबित करने के लिए कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि उसे इन स्कूलों की यूनिफॉर्म बेचने का अधिकार किस आधार पर मिला है। प्रशासन ने कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन और यूनिफॉर्म बिक्री में एकाधिकार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।

आईआईटी मुंबई सिंहस्थ के कामों के लिए ट्रेनिंग देगा, सुरक्षित निर्माण पर फोकस

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • आगामी सिंहस्थ को लेकर उज्जैन में 15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास और निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कामों को समय पर, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए सिंहस्थ मेला कार्यालय में शुक्रवार से दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसमें आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर इंजीनियरों, सुपरवाइजरों और श्रमिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के पहले चरण में आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर अल्बर्ट और प्रोफेसर वरुण कुमार 100 से अधिक इंजीनियरों और सुपरवाइजरों को साइट प्रबंधन, निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। पहले दिन करीब 50 इंजीनियरों ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दूसरे चरण में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों को भी सुरक्षा और कार्य गुणवत्ता से जुड़े जरूरी उपाय सिखाए जाएंगे।

प्रशिक्षण प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश हैं कि सिंहस्थ से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरी सुरक्षा के साथ पूरे किए जाएं। फिलहाल 100 से अधिक निर्माण स्थल सक्रिय हैं। हर साइट की अलग तकनीकी जरूरतों को देखते हुए आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, ताकि निर्माण कार्यों में किसी तरह की दुर्घटना या लापरवाही न हो और सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।

सीडीआर टावर डंप तकनीक से आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन • सबसे व्यस्त और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र फ्रीगंज में दो मोबाइल शोरूम से करीब 70 लाख रुपए के प्रीमियम स्मार्टफोन चोरी होने के मामले में एक सप्ताह बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। 11 जुलाई की रात हुई इस वारदात के आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच तेज कर दी है। माधव नगर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम अब टेलीकॉम कंपनियों की मदद से सीडीआर और एसडीआर टावर डंप डिटेल के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस घटना वाली रात 2 बजे से 3 बजे के बीच फ्रीगंज क्षेत्र के मोबाइल टावरों से जुड़े सभी सक्रिय मोबाइल नंबरों का डेटा जुटा रही है। इस सूची का विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि वारदात के समय क्षेत्र में कौन-कौन से संदिग्ध मोबाइल नंबर सक्रिय थे।

अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और टावर डंप से मिले तकनीकी डेटा का मिलान किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन किए चोरी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर पूरी तैयारी और रेकी के साथ आए थे। उन्होंने दोनों दुकानों में केवल महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोनों को ही निशाना बनाया। पुलिस के अनुसार 'हाई चॉइस'

मोबाइल शोरूम से करीब 45 और 'एसएस मोबाइल' से लगभग 50 प्रीमियम ब्रांड के स्मार्टफोन चोरी किए गए। वारदात के दौरान आरोपियों ने दुकानों के कांच भी तोड़ दिए थे।

व्यापारियों में नाराजगी

फ्रीगंज जैसे अत्यंत व्यस्त कारोबारी इलाके में हुई इस बड़ी चोरी ने शहर के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। घटना के एक सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाली दुकानें सील, पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

देवास • स्कूल और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 दुकानों को सील कर दिया। करीब दो घंटे तक चले इस अभियान से शहरभर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई एसडीएम अभिषेक शर्मा और सीएसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में की गई।

अधिकारियों ने खुद की जांच

अभियान के दौरान कई दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से भाग निकले, लेकिन अधिकारियों ने दुकानें खुलवाकर जांच कराई। एसडीएम अभिषेक शर्मा और सीएसपी सुमित अग्रवाल ने स्वयं दुकानों के भीतर जाकर निरीक्षण किया। जिन दुकानों में सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पाद मिले, उन्हें तत्काल सील कर दिया गया।

स्कूलों के आसपास चला अभियान

टीम ने सबसे पहले केपी कॉलेज और राधाबाई स्कूल क्षेत्र में कार्रवाई की, जहां तंबाकू उत्पाद मिलने पर दुकानें सील की गईं। इसके बाद नाहर दरवाजा क्षेत्र में तीन दुकानों पर कार्रवाई हुई। कोतवाली क्षेत्र में चिमनाबाई, शिशु विहार सहित अन्य स्कूलों के आसपास चार दुकानों को सील किया गया। इटावा क्षेत्र में भी दो से तीन दुकानों पर कार्रवाई की गई।

पुलिस बल रहा तैनात

अभियान के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, नाहर दरवाजा थाना प्रभारी आलोक सोनी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सघन अभियान आगे भी लगातार चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

भोजशाला के बाहर नमाज कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद जगह ढूंढ रहा प्रशासन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● भोजशाला परिसर के बाहर शुक्रवार को जुमे की नमाज होना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश दिया था। अब इसका लिखित आदेश शुक्रवार सुबह जारी हो गया है। इसके बाद प्रशासन इसकी जगह तलाश रहा है। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी। इसमें अंतरिम आदेश हुए कि नमाज के लिए शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच जगह दी जाए। यह खुले में भोजशाला परिसर से सटकर या फिर निकट हो। इसके बाद से ही नमाज की जगह को लेकर उलझन चल रही थी। अब शुक्रवार सुबह लिखित आदेश आ गया है।

धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि अभी लिखित आदेश आया है और इसका अध्ययन करने के साथ ही जगह भी देखी जा रही है। जल्द इसमें फैसला करेंगे।

भोजशाला मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निम्न निर्देश दिए।

मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज हेतु दोपहर 1 से 3 बजे के मध्य समीप ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए। भोजशाला मां सरस्वती मंदिर में मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने से इनकार किया। भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष की पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला मां वाग्देवी की निरंतर पूजा जारी रहेगी। हिंदू पक्ष के हित में हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया गया। न्यायालय की अनुमति के बगैर एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश। अंतिम बहस हेतु 5 अगस्त 2026 नियत।

इन्होंने की पैरवी–हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विनय जोशी, रंजीत कुमार, सी.एस. वैद्यनाथन, पार्थ यादव, सौरव सिंह और मणि मुंजाल ने पैरवी की।

इस केस में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री सहित आशीष गोयल, आशीष जनक, मोहित गर्ग और सुनील सारस्वत को प्रतिवादी बनाया गया है। यह जानकारी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष और भोजशाला मामले के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दी।

एयरपोर्ट विस्तार पर पहले सांसद लालवानी की मांग, अब पूर्व सांसद महाजन की सीएम को चिट्ठी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● एयरपोर्ट विकास को लेकर जो मांग सांसद शंकर लालवानी ने एक दिन पहले 15 जुलाई को सीएम डॉ. मोहन यादव से मंच से की, उसी पर अब पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने चिट्ठी लिख दी। इसे अब आगे श्रेय की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर के एयरपोर्ट का विस्तार होना है। इसके लिए लंबे समय से मास्टर प्लान बना हुआ है। लेकिन काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। आगे सिंहस्थ 2028 की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। जिसके चलते एयरपोर्ट के विस्तार की मांग तेज होने के साथ-साथ इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सांसद शंकर लालवानी ने 15 जुलाई को सीएम डॉ. मोहन यादव से मंच पर जो मांग की। उसी पर अब पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने भी चिट्ठी लिखी है।

महाजन ने 16 जुलाई को यह चिट्ठी सीएम डॉ. मोहन यादव को लिखी है। इसमें कहा गया कि यह प्रदेश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। समाचार में पढ़ा कि उज्जैन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मैंने इसके विस्तार के लिए बहुत प्रयास किए। इसके चलते कई काम हुए। आगे विस्तार के लिए जमीन की मांग की गई है। विकास के लिए सर्वे होने के बाद भी शासन की ओर से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि विस्तार के लिए जमीन शीघ्र एयरपोर्ट अथारिटी को हस्तांतरित की जाए। अब राजनीतिक गलियारे में बात उठ रही है कि आखिर पूर्व सांसद ने चिट्ठी क्यों लिखी। इसकी मांग तो वर्तमान सांसद उठा चुके हैं और एयरपोर्ट अथारिटी की बैठकों में भी यह बात हो रही है। इस चिट्ठी को राजनीतिक नजरिए से और आगे भविष्य में श्रेय की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

सांसद लालवानी ने क्या रखी थी बात

उधर 15 जुलाई को जब एयरपोर्ट पर इंदौर से आबूधाबी फ्लाइट का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ, तब सीएम मंच पर थे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि एयरपोर्ट इंदौर की क्षमता 40 लाख यात्रियों की है और इस साल 43 लाख यात्रियों ने इंदौर से सफर किया। ऐसे में अब विस्तार की जरूरत है। आगे सिंहस्थ है और इंदौर के आसपास औद्योगिक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। विस्तार के लिए मास्टर प्लान तैयार है इसमें नया टर्मिनल प्रस्तावित है, टैक्सी वे, नए एयर स्ट्रिप जो बोइंग जैसे बड़े विमान के लिए जरूरी है, इन सभी के लिए 143 एकड़ जमीन चाहिए, इसके लिए अधिकरियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। यह जमीन जल्द मिल जाएगी तो सिंहस्थ के पहले टर्मिनल का शुभारंभ हो सकेगा।

आबकारी एसी मंदाकिनी दीक्षित मामले में हाईकोर्ट डीबी की सिंगल बेंच आदेश पर सख्त टिप्पणी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● निलंबित आबकारी सहायक आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित को हाईकोर्ट डबल बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगने के साथ ही सीबीआई में दर्ज एफआईआर और जांच को भी रद्द करने के आदेश हुए। साथ ही डीबी ने सिंगल बेंच के आदेश पर सख्त टिप्पणी की है। इंदौर में रहने वाले शराब ठेकेदार ने देवास में शराब की दुकान ली थी। बाद में मकवाना ने सुसाइड कर लिया। इसके कुछ दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप लगाए कि वह परेशान करती है और हर दुकान से डेढ़ लाख प्रति माह रिश्वत मांगती है। अभी तक 22 लाख ले चुकी है।

इस मामले के बाद दीक्षित को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मकवाना की मां संतोष बाई ने पुलिस जांच में ढिलाई के आरोप लगाकर याचिका दायर की। इसमें सिंगल बेंच ने सीबीआई को एफआईआर करने और जांच करने के आदेश दिए। सीबीआई जांच भी शुरु हो गई। दीक्षित इसके खिलाफ रिट अपील में गई। इसमें यह आदेश हुआ है। जस्टिस संदीप भट्ट और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर तीखी टिप्पणी की है। इसमें कहा गया कि सिंगल बेंच ने वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध शिकायत को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में दर्ज करने का सीधा निर्देश देकर गलती की है। यह निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 156 (या बीएनएसएस की धारा 194) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

स्कीम-172 सुपर कॉरिडोर पर पीपीपी मॉडल पर बनने वाला है प्रोजेक्ट

500 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए नहीं मिल रही कंपनी, दोबारा होगी टेंडर की प्रक्रिया

- 11 हेक्टेयर में बनना है कन्वेशन सेंटर भवन
- प्री-बिड मीटिंग में दो कंपनियां हुई थी शामिल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● स्कीम-172 सुपर कॉरिडोर पर आईडीए द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक कन्वेंशन-कम-एग्जीबिशन सेंटर बनाने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एजेंसी नहीं मिलने से अब दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी। भारी-भरकम खर्च की इस परियोजना के लिए हुई प्री-बिड मीटिंग में जरूर दो कंपनियां शामिल हुई थीं, लेकिन टेंडर के लिए यह कंपनियां भी सामने नहीं आई। कन्वेशन सेंटर के लिए 17 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है, जिसमें 11 हेक्टर भूमि कन्वेशन सेंटर के भवन एवं 6 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। लगभग 545 करोड़ रुपए में विकसित होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति नहीं मिल सकी। संभावना है कि इस बार कुछ बदलाव के बाद एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया की जा सकती है।

प्री-विड मीटिंग में शामिल हुए थे दो डेवलपर

कन्वेंशन सेंटर के लिए गत 21 अप्रैल को आइडीए कार्यालय में प्री बिड मीटिंग आयोजित हुई थी। इसमें दो डेवलपर शामिल हुए थे। ग्रुप के पदाधिकारियों ने आइडीए सीईओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इससे संभावना थी कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए एजेंसी मिल जाएगी। हालांकि पहले चरण की प्रक्रिया में किसी ने भी इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं दिखाई।

45 साल रखरखाव का जिम्मा

हाल ही में हुई टेंडर प्रक्रिया में पूरी परियोजना का निर्माण तीन साल में करना था। साथ ही डेवलपर को 45 वर्ष तक रखरखाव का जिम्मा भी मिलता। इस दौरान प्रोजेक्ट का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन डेवलपर के पास रहता। कंसेशन अवधि समाप्त होने के बाद विकसित कन्वेंशन सेंटर आइडीए को वापस सौंपना था, जबकि छह हेक्टेयर व्यावसायिक हिस्से में डेवलपर को फ्री-होल्ड अधिकार मिलते। इसका वह अपने हिसाब से उपयोग कर सकता था।

महिंद्रा के डीलर सौम्या व्हीकल्स पर 20 हजार का जुर्माना

एमआरपी से ज्यादा में बेचा ऑयल

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अधिकृत डीलर सौम्या व्हीकल्स को अपने वर्कशॉप से MRP से ज्यादा पर ऑयल बेचना भारी पड़ गया। इस संबंध में ग्राहक ने नाप-तौल विभाग में शिकायत की थी। अब सौम्या व्हीकल्स 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

इंदौर में देवास नाका पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के अधिकृत डीलर सौम्या व्हीकल्स का शोरूम और वर्कशॉप है। यहां से एक ग्राहक ने ऑयल खरीदा था जिसके पैकेट पर कीमत 110 रुपए लिखी थी, लेकिन इसे 140 रुपए में बेचा गया। इसकी शिकायत हुई और अब इस पर विभाग ने 20 हजार का जुर्माना ठोका है।

बता दें कि यह शिकायत ग्राहक प्रथम जायसवाल ने की थी। जायसवाल ने यह शिकायत जागरूक उपभोक्ता समिति के मुकेश अमोलिया को दी थी। उन्होंने शिकायत नापतौल विभाग (मध्यप्रदेश नापतौल विभाग) में की। इसमें विभाग के निरीक्षक केएस ठाकुर ने जांच की और इसके बाद उप नियंत्रक संजय पाटणकर ने इसमें 20 हजार का जुर्माना लगाया।

इसमें कंपनी की डायरेक्टर श्वेता अग्रवाल और बिहारीलाल पोद्दार के साथ ही शरद यादव (सेल्स एग्जीक्यूटिव) और कंपनी सौम्या पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस आदेश के बाद सभी ने चालान के जरिए यह राशि जमा कर दी है।

जिला अस्पताल के लिए स्टाफ शिफ्टिंग से लड़खड़ाई व्यवस्था

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● धार रोड स्थित नए जिला अस्पताल के संचालन की तैयारियों के बीच शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है। जिला अस्पताल में स्टाफ और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के लिए विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से कर्मचारियों की शिफ्टिंग कर दी है।

इससे पीसी सेठी अस्पताल और हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और अधिक महसूस होने लगी है। पीसी सेठी अस्पताल पहले से ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव से जूझ रहा है। अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और सर्जनों के कई पद रिक्त हैं। वर्तमान में केवल दो नियमित गायनाकोलॉजिस्ट के भरोसे सेवाएं संचालित हो रही हैं। यहां हर महीने औसतन 400 से 500 प्रसव होते हैं, जबकि ओपीडी में प्रतिदिन 400 मरीज पहुंचते है। मेडिको-लीगल ऑपरेशन और केस (एमएलसी) जैसी जिम्मेदारियां भी सीमित चिकित्सकीय स्टाफ पर ही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बढ़ते कार्यभार के कारण सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

रोजाना ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की जिला अस्पताल में तैनाती के बाद हुकुमचंद अस्पताल की स्थिति और कमजोर हुई है। खासकर शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी के चलते मरीजों को अन्य अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि जिला अस्पताल के लिए भेजे गए विशेषज्ञों के स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं की गईं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

क्रेडाईका दावा- विकास शुल्क संबंधी नियम दोबारा लागू नहीं हो सकता, प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं

आश्रय निधि नियम पर कारोबारी कोर्ट जाएंगे, निगम ने भी दायर की केविएट

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● नगर निगम द्वारा वर्ष 2021 में नगरीय प्रशासन विभाग के आश्रय निधि नियम को लागू किए जाने के बाद रियल एस्टेट कारोबारियों और निगम प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। निगम ने इस नियम के तहत 200 से अधिक बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं और मामले को लेकर न्यायालय जाने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं, नगर निगम ने भी संभावित कानूनी कार्रवाई को देखते हुए केविएट याचिका दायर कर दी है। नियम के अनुसार, पहले से विकसित कॉलोनियों अथवा निजी भूखंडों पर बहुमंजिला इमारत निर्माण से पहले विकास अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके तहत बिल्डर को कुल प्रकोष्ठों का 15 प्रतिशत आश्रय निधि प्रावधान के अनुसार आरक्षित रखना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल का कहना है कि लागू किया गया नियम पूरी तरह वैधानिक है। उनके अनुसार, बड़े भूखंडों पर बनने वाली बहुमंजिला परियोजनाएं कॉलोनी की श्रेणी में आती हैं, इसलिए उनके लिए विकास अनुमति लेना अनिवार्य है। जो बिल्डर बिना विकास अनुमति के निर्माण कर रहे हैं, उन्हें ही नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम ने इस मामले में विधिक राय भी प्राप्त की है और न्यायालय में केविएट याचिका भी दायर कर दी है।

फाइल फोटो

इंदौर क्रेडाई के अध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि वर्ष 2021 में बना नियम अब पांच वर्ष बाद प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। उनका तर्क है कि कॉलोनाइजर पहले ही टाउन एंड कंट्री प्लानिग विभाग से लेआउट स्वीकृति, नगर निगम से बिल्डिग परमिशन और कॉलोनी विकास अनुमति के दौरान आश्रय प्लॉट, प्रकोष्ठ अथवा आश्रय शुल्क का भुगतान कर चुका होता है।

इंदौर में नर्मदा के चौथे चरण में नई लाइनें बिछेंगी, पुरानी बदलेंगे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में जल प्रदाय और सीवरेज के 1214.54 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) से मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एपेक्स कमेटी ने इस परियोजना को स्वीकृति दी है। इसमें 907.74 करोड़ रुपए की जल प्रदाय और 306.80 करोड़रुपए की सीवरेज परियोजनाएं शामिल हैं।

302.70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सहायता के रूप में देगी – कुल परियोजना लागत का 25 फीसदी यानी करीब 302.70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सहायता के रूप में देगी। यह राशि नर्मदा परियोजना के चौथे चरण के तहत जल वितरण लाइन बिछाने और शहर में सीवरेज नेटवर्क विस्तार पर खर्च होगी। निगम के अनुसार पहले इस परियोजना के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए का ऋण लेने की योजना थी, लेकिन केंद्र से मिलने वाली सहायता और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के बाद अब करीब 300 करोड़ रुपए का ही ऋण लेना पड़ेगा।

तीन हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भेजे गए थे बैठक में मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, यूडीडी के दिव्यांक सिंह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

नेहरू पार्क बना अटाला उद्यान, कई जगह लोहे का भंगार और मिट्टी बिल्डिंग मटेरियल के लगे ढेर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर का सबसे पुराना कमला नेहरू पार्क एक तरह से वेस्ट मटेरियल और भंगार उद्यान बनता जा रहा है। यहां पर कई वर्षों से काम चल रहा है लेकिन काम कब पूरा होगा यह कोई नहीं बता पा रहा है। नेहरू पार्क में लोहे भंगार। आदि के वेस्ट मटेरियल के साथ बिल्डिंग मटेरियल का सामान भी काफी पड़ा हुआ है, जिसमें न तो सफाई हो पा रही है और न ही इस तरह का टाला हटा रहे हैं। बताते हैं कि नेहरू पार्क में स्मार्ट सिटी के माध्यम से कई काम करोड़ों रुपये के किए गए थे, लेकिन यहां पर एक तरह से देखा जाए तो सीमेंट कांकीट का जंगल बना दिया और उद्यान कम सीमेंट क्रांकीट का निर्माण अधिक है। इस पर भी कचरा वाहन खड़े रहते हैं तो यहां पर चार्जिंग स्टेशन भी बना दिया। वह भी वाहन खड़े रहते हैं। इसके बाद यहां पर लोहे आदि का भंगार सामान पटकना शुरू कर दिया, जिसका अब यहां बड़ा ढेर बन गया है। नेहरू पार्क उद्यान में स्विमिंग पूल का काम चल रहा है जिसका अटाला अलग पड़ा हुआ है। यहां पर अन्य निर्माण कार्य जारी है जिसका बिल्डिंग मटेरियल का अटाला अलग है। कोई जिम्मेदार अफसर बताने को तैयार नहीं है कि काम कब होगा? और अटाला कब हटेगा ? लेकिन यहां पर अब लोग सैर सपाटे के लिए आने कम हो गए हैं। रविवार के दिन शाम के समय जरूर कभी कभार लोग आते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।